तहत सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित राणा प्रताप सागर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट की निरन्तर खराबी की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। यह प्रोजेक्ट भारत तथा कनाडा दोनों के सहयोग से तैयार हुआ था जिसकी एक यूनिट की क्षमता 220 मैगावाट थी। यह प्रोजेक्ट अपने प्रारम्भिक काल में केवल तीन महीने अधिकतम चला। उसके बाद से इसमें बराबर कोई न कोई खराबी आती रही। इसमें "हैवी वाटर" के रसाव की वजह से इस को बन्द कर दिया गया है।

कैनेडियन सरकार से बनाने में सहयोग तो हमने लिया पर इसके सुधार की तकनीकी पर अभी तक शायद हम काबू नहीं पा सके हैं, इसीलिए इसकी एक यूनिट जिसकी क्षमता 220 मैगावाट है, पूर्णतया बन्द है। इससे राजस्थान राज्य की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को भारी आघात लगा है। राज्य के उद्योग तथा कृषि को भारी नुकसान हुआ है।

मैं सरकार से मांग करूंगी कि यहां रावतमाटा में परमाणु बिजली संयत्र का ढांचा तो पहले से ही तैयार है। यहां पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से दो परमाणु ऊर्जा सयंत्र और लगाये जा सकते हैं। कृपया इसे अतिआवश्यक समझकर राजस्थान जैसे पिछड़े प्रांत की अर्थव्यवस्था को बिगड़ने से बचावें।

SHRI SATISA AGARWAL (Jaipur): This is an important issue regarding a power project in Rajasthan. We are all with you.

(v) Need to harness the development potential of Jammu and Kashmir State

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla): The Jammu & Kashmir State deserves special attention in so far as its overall development is concerned. It has lagged behied in industrial development as is evident from the fact that it received 0.06 per cent of the investment made by the Central Government for Public Sector industries since independence. The Stase has not benefited satisfactorily from the development of railways as is evident from the fact that even after a favourable survey report, the railway line could not be laid between Gazigund and Baramulla. The State has vast hydel power which has not been harnessed to the advantage not only of the State, but to the advantage of the country. There is need to harness the State's potential for sizeable development in the State so that it compares favourably with other States in India.

(vi) Need to provide more Telephone facilities in certain areas of Madhya Pradesh

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, देश में और मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के लिए काफी समय तक प्रतिक्षा करनी होती है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इन्दौर, उज्जैन सहित अनेक नगरों में कई-कई वर्षों से लोग टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतिक्षा-रत हैं। टेलीफोन केन्द्रों के विस्तार का कार्यक्रम अपेक्षा और मांग के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। उज्जैन, रतलाम, नीमच के दूरभाष केन्द्र के विस्तार कार्य कई वर्षों से पूरे नहीं हुए हैं। इसके कारण जनता को टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। आलोट से ताल के बीच की सीधी दूरभाष सेवा उपलब्ध नहीं है जबकि ताल आलोट एक ही तहसील में हैं। गांवों में पी० सी० ओ० तथा छोटे टेलीफोन केन्द्रों को अधिक संख्या में खोले जाने की आवश्यकता है जिससे गांवों का नगरों से सीधा सम्पर्क हो सके।

दूरभाष केन्द्रों को अधिक कार्यक्षम

[श्री सत्यनारायण जटिया]

बनाने की आवश्यकता है। कर्मचारियों की कमी की समुचित मात्रा में नियुक्ति कर दूरभाष केन्द्रों की कार्य क्षमता बढ़ाने से उपभोक्ताओं को यथोचित सेवा प्राप्त कराना चाहिए।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि दूरभाष सेवा को अधिक कार्यक्षम बनाने हेतु पर्याप्त उपाय किये जाएं तथा उज्जैन, रतलाम, नीमच के दूरभाष केन्द्रों का विस्तार कर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

(vii) Need to shift the present telegraph office at Burdwan and to open some more Telegraph offices there

SHRI SUSHIL BHATTACHARYYA (Burdwan) : I would like to invite immediate attention of the Government to the insufferable inconvenience caused to the public in the absence of an adequate number of telegraph offices in the city of Burdwan. The only tetegraph office which is supposed to serve more than three lakhs of people is at present accommodated in the first floor of a rented house in a blind alley. The rent is out of all proportion to the accommodation provided for and that too, in an ill-ventilated building, the roof of which collapsed recently. Burdwan, besides being the district headquarters, is a growing city of importance having a university campus within the city and with far-flung area requires pretty badly a telegraph office in each zonal postal area. The present telegraph office, too, needs, to be moved to the telephone exchange building for greater convenience of customers.

(viii) Need to lay down norms aud guidelines for the distribution of loans by banks under mass loaning scheme

DR. A. KALANIDHI (Madras Central) : Under the 20-Point Programme, nationalised banks are being asked to arrange to find out eligible unemployed youths for disbursement of loans. Though there are no norms nor guarantors for such loans, yet the Managers of the branches of the Banks are held responsible for their failure to recover the loans disbursed. The managers are not given enough time to scrutinise the applications received by them and they are compelled to disburse the loans within a short time. By this kind of loan disbursement, the interets of the depositors are not safeguarded and people will lose their faith in the banking system. It is understood that a sum of Rs. 46.00 crores is to be disbursed in each State. Thus a colossal amonut will be involved in this kind of disbursement of loans, without taking any security for the same. I, therefore, request that certain guidelines and rules be framed for disbursement of loans by the Government and the interests of the depositors as well as the Government be safeguarded. The banks should be given a free hand to choose the prospective loanees to ensure the repaying of the disbursed loans and utilisation of the loan amount towards productivity and employment to the unemployed youths.

(ix) Need to provide drinking water in Barmer, Jaisalmer and Jodhpur districts

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त के थार रेगिस्तानी क्षेत्रों विशेषत: बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में पीने के पानी की समस्या राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपये व्यय करने के उपरान्त भी अभी तक आधे से अधिक ग्रामों में गंभीर से गंभीरतम बनी हुई है।

उक्त जिलों में तिहाई हिस्से में नजदीक में पानी का कोई स्रोत नहीं है जो नलकूप बनाये गये हैं उनमें से अधिकांश में बहुत